लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक : 16 - 28 फरवरी 2023 www.haryanasamvad.gov.in अंक - 60

"मन में नकारात्मक विचार आ रहे हों तो किताबें आपको सकारात्मकता की ओर ले जाने का काम करती हैं।"

: स्वामी दयानंद

अमृतकाल का 'निर्मल' बजट

3

'मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना' में 26 नई सब्जियां व फल शामिल

6

सुशासन से निकली शिक्षा संस्कृति

8

आध्यात्मिक चिंतन के साथ सामाजिक विकास

बहोडा कलां स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

विशेष प्रतिनिधि

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत जी-20 की अध्यक्षता करते हुए सामाजिक व आर्थिक उत्थान में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। संस्कारों के समावेश के साथ भारत की पहचान दुनिया में कायम हो रही है। देश निरन्तर बदल रहा है और आज आर्थिक समृद्धि के साथ विश्व के पांचवें पायदान पर भारत दुनिया में अग्रणी बन रहा है।

राष्ट्रपति गुरुग्राम जिला के बहोडा कलां में स्थित ब्रह्माकुमारी ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 'वूमेन एज फाउंडेशन ऑफ़ ए वैल्यू बेस्ड सोसाइटी' विषय पर आयोजित नेशनल कन्वेंशन को संबोधित कर रही थी। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में पहुंचने पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। ओम शांति रिट्रीट सेंटर परिसर में राष्ट्रपति ने स्प्रिचुअल आर्ट गैलरी और 2डी रंगोली का अवलोकन भी किया।

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि समाज में महिला सशक्तिकरण के लिए जहां सरकार अपना दायित्व निभा रही हैं, वहीं प्रत्येक व्यक्ति को नारी शक्ति का सम्मान करते हुए उनकी कार्यशैली से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज विश्व स्तर पर भारत संस्कारों के बल पर अपना प्रभुत्व कायम कर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि आध्यात्मिक चिंतन के साथ सामाजिक विकास की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मूल्यों आधारित समाज की संरचना की जा रही है। उन्होंने ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय संस्थान द्वारा समाज हित में किये जा रहे कार्यों व आत्मिक चिंतन का संदेश जन जन तक पहुंचाने में निभाई जा रही भूमिका की सराहना की।

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। चाहे विज्ञान, कला, शिक्षा, इंजीनियरिंग या राजनीतिक क्षेत्र की बात क्यों न हो, महिलाओं ने हर स्तर पर अपनी कामयाबी के झंडे बुलंद किए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं से ही एक परिवार आदर्श परिवार बनता है और आदर्श परिवार से ही एक आदर्श समाज का निमार्ण होता है। इसलिए महिलाएं समाज में बेहतर बदलाव ला सकती हैं।

नैतिक मूल्यों के समावेश में महिलाओं की अहम भूमिकाः राज्यपाल

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना और सुधार में महिलाओं की अहम भूमिका है। हमारे शास्त्रों में नारी को देवी का स्वरूप मानते हुए कहा गया है जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। समाज में माता-बहनों का त्याग, तपस्या, संयम और समर्पण भाव अतुलनीय है।

समग्र विकास को गति देगा बजट

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार भी प्रदेश के लिए अमृत काल का पहला बजट पेश करेगी, जिससे प्रदेश में सबकी भागीदारी से सर्वांगीण विकास हो। वर्ष 2023-24 के राज्य के आम बजट में किसानों, मजदूरों, उद्योगों, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने सहित अंत्योदय परिवारों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान पर फोकस किया जाएगा। यह बजट हर वर्ग के कल्याण के लिए होगा।

मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों व विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया और पिछले वर्ष के बजट घोषणाओं पर समीक्षा की गई। केंद्रीय बजट में महत्वपूर्ण परियोजनाओं से भी हरियाणा को अधिक से अधिक लाभ मिले, इस बारे में भी चर्चा की गई।

मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भारतीय अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के विजन को प्राप्त करने में हरियाणा अपना पूरा योगदान देगा। इसके लिए हर सेक्टर में ग्रोथ बढ़ाने की जरूरत है। इसी कड़ी में लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। याद रहे 20 फरवरी को हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आरंभ होगा।

सूरजकुंड मेले में हुआ एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन

सूरजकुंड मेले में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' का दर्शन देखने को मिला। देश -विदेश के कलाकारों व शिल्पकारों की कल्पनाओं से सराबोर कलाकृतियों से सुसज्जित हस्तशिल्प मेले की छटा देखते ही बनती रही।

मेले में हर वर्ष एक सहभागी राष्ट्र और एक 'थीम स्टेट' होता है। मेले में इस वर्ष संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन सहभागी राष्ट्र रहा। मेले में संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सहभागी राष्ट्र तथा भारत के आठ उत्तर-पूर्वी राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल रहे। इन राज्यों ने एक साथ मिलकर एक ही मंच पर अपनी कला, हस्तशिल्प का बेहतरीन प्रदर्शन किया।

इस वर्ष करीब 40 देश मेले का हिस्सा रहे। इनमें शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शामिल हैं, जिसके तहत कजाकिस्तान, चीन, रूस, उजबेकिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया

जैसे 25 से अधिक देश शामिल हैं। तुर्की, कंबोडिया, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, सऊदी अरब, कतर जैसे कुछ नाम बहुत उत्साह के साथ भाग लेंगे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेला देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता में भी योगदान देता है। हम सभी को देश के शिल्पकारों द्वारा बनाई गई वस्तुओं पर गर्व करना चाहिए और उनके द्वारा बनाये गये उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा करके हम आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में मुख्य चौपाल पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या के मौके पर फैशन शो का आयोजन हुआ। शिल्प मेले से न केवल देश-दुनिया के लोगों को रोजगार मिला है बल्कि शिल्पियों को कला और संस्कृति दिखाने का मौका भी मिला।

विरासत सांस्कृतिक प्रदर्शनी में हरियाणा की बुणाई कला विशेष रूप से लोकप्रिय रही। हरियाणा का आपणा घर में लगाई गई सांस्कृतिक प्रदर्शनी में हरियाणवी बुणाई कला के नमूने के रूप में चारपाइयां, खटौले एवं पीढ़े पर्यटकों को आकर्षण का केंद्र रहे।

हरियाणवी लोकजीवन में बुणाई कला का विशेष महत्व है। पीढ़ों के अंदर रस्सी की गई बुणाई के डिजाईन यहां की लोक सांस्कृतिक परम्परा को दर्शाते हैं। इन डिजाईनों में लहरिया, पगड़ंडियां, चौपड़, फूल-पत्तियां आदि शामिल हैं।

-संवाद ब्यूरो

संपादकीय

सूरजकुंड मेले की महक

केंद्रीय राजधानी की सीमा पर स्थित हरियाणा पर्यटन स्थल सूरजकुंड इन दिनों 36वें सूरजकुंड-अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का केंद्र बना हुआ है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में 'मिनिस्ट्री ऑफ डवलपमेंट ऑफ नार्थ ईस्ट' का क्षेत्र 'इंटरनेशनल ईयर आफ मिलेट्स 2023 का एक ब्रोशर' भी लांच किया।

उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर आफ मिलेट्स 2023 घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विभिन्न अवसरों पर मोटे अनाज के प्रयोग करने का आह्वान कर रहे हैं।

हरियाणा सरकार भी मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रही है। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेले में भी बाजरे से तैयार कई स्वादिष्ट व स्वास्थ्यवर्धक व्यंजन तैयार किए गए हैं।

मेले के लिए वह दिन और भी खास रहा, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे मंत्रिमण्डल व सभी विधायकों के साथ राजहंस होटल में दोपहर का भोजन किया। इस दौरान मेले में सांस्कृतिक महाकुंभ भी देखने को मिला, जब विदेशी कलाकारों ने अपनी कला एवं संस्कृति का प्रदर्शन किया।

अलग-अलग भाव, पहनावे, म्यूज़िक तथा बोल सुना कर विदेशी कलाकारों ने दुनियाभर की सांस्कृतिक विविधताओं से माहौल को गुंजायमान कर दिया। सभी ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में शास्त्रीय से लेकर लोक संस्कृति तक अपनी प्राचीन परंपराओं को सजीव कर दिया। स्टेज पर जी-20 की थीम- एक धरा, एक परिवार, एक भविष्य की स्पष्ट झलक देखने को मिली।

ऐसे मेले हमारी लोक सांस्कृतिक को ही अनूठी पहचान नहीं देते, बल्कि ग्रामीण-पर्यटन एवं सांस्कृतिक-पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं। आपको स्मरण होगा कि इस सूरजकुंड मेले की शुरुआत एक सीमित स्वरूप में 36 वर्ष पूर्व आरंभ हुई थी और अब यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित एवं लोकप्रिय मेले का रूप ले चुका है।

-डॉ. चन्द्र त्रिखा

हरियाणा में निवेश के लिए अनुकूल माहौल

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों को प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया और आश्वासन दिया कि राज्य सरकार की ओर से उन्हें कारोबार करने व निवेश संबंधी सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। हरियाणा में उद्योग एवं निवेश के लिए अनुकूल माहौल है, जिसकी बदौलत हरियाणा आज निवेश के लिए प्रमुख गंतव्य बन गया है।

बाताया कि वर्ष 2019 के बाद से, प्रदेश में 5.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ है। निर्यात बढ़कर 2.17 लाख करोड़ रुपए हो गया है। बैठक में रूस, बेलारूस, तज्जाकिस्तान, कम्बोडिया, सऊदी अरब, मालदीव, चीन, क्रिगीस्तान, उज़्बेकिस्तान, नेपाल, कज़ाकिस्तान, आर्मेनिया, म्यांमार, कतर, ईरान, यूएई, बहरीन देशों के प्रतिनिधिमंडल उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा तेजी से विकास करने वाले राज्यों में शुमार है। हरियाणा बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी), बिजनेस टू कस्टमर (बी2सी) और सरकार से सरकार (जी2जी) के अलावा हार्ट टू हार्ट (एच2एच) कनेक्शन यानि दिल से दिल के साथ व्यापार करने में विश्वास करता है।

राज्य ने बनाई वैश्विक मानचित्र पर पहचान

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा आर्थिक, खेल महाशक्ति और विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और घरेलू व विदेशी निवेशक भी आज हरियाणा की ओर देख रहे हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा ने तेजी से प्रगति की है, जिसकी बदौलत राज्य ने वैश्विक मानचित्र पर अपनी पहचान बनाई है।

गुरुग्राम में आईआईएम, रोहतक द्वारा जी-20 अध्यक्षता को लेकर आयोजित कार्य' म मनोहर लाल ने कहा कि भारत की जी-20 अध्यक्षता का थीम वसुधैव कुटुम्बकम है, जिसका अर्थ है 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य', जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेखांकित किया गया है। इसका उद्देश्य विकसित और उभरते देशों के बीच समावेशी सहयोग को प्रेरित करना और सामूहिक एवं सहयोगात्मक कार्रवाई के महत्व को पहचाना है।

देश की जीडीपी में हरियाणा का योगदान 3.87 फीसदी : मुख्यमंत्री ने क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा देश में 21वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से 18वें स्थान पर है, लेकिन हरियाणा देश के सकल घरेलू उत्पाद में 3.87 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। इतना ही नहीं, राज्य देश के निर्यात में 4 प्रतिशत का योगदान करता है। हरियाणा बासमती चावल, ऑटो और ऑटो घटकों, मानव निर्मित फाइबर, कालीन, इलेक्ट्रिक मशीनरी आदि जैसी वस्तुओं का निर्यात करने वाला देश का 7वां सबसे बड़ा माल निर्यातक है।

ग्रामीण विकास के लिए जारी रहेगी ई-टेंडरिंग व्यवस्था

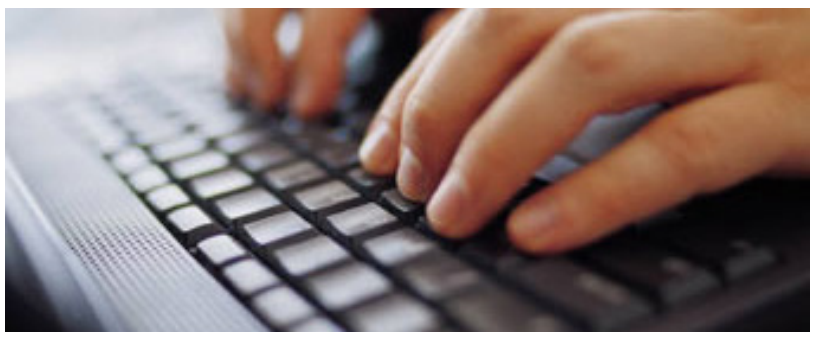

हरियाणा सरकार द्वारा गांव में विकास कार्यों में तेजी लाने व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई ई-टेंडरिंग व्यवस्था जारी रहेगी। ई-टेंडरिंग व्यवस्था के विरुद्ध कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका पर उच्च न्यायालय ने स्टे देने से इनकार कर दिया है। उच्च न्यायालय ने माना है कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई यह व्यवस्था पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा और सकारात्मक कदम है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक स्वायत्ता प्रदान करते हुए उनकी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है। अब पंचायती राज संस्थाएं अपने फंड व ग्रांट इन ऐड से छोटे या बड़े, चाहे जितनी भी राशि के काम हों, करवा सकती हैं। दो लाख रुपए से अधिक के विकास कार्य ई-टेंडर के माध्यम से होंगे, जिससे न केवल कार्यों में तेजी आएगी बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी और ग्रामीणों को भी विकास कार्यों की जानकारी मिलती रहेगी।

मुख्यमंत्री द्वारा इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में गांवों में विकास कार्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं को 1,100 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इसमें से 850 करोड़ केवल पंचायतों को दिया गया है। नई पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पारित कर विकास कार्य भी शुरू करवा दिए गए हैं।

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
स्टाफ राइटर : संगीता शर्मा
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छाया हरियाणा

मध्य प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का शानदार प्रदर्शन रहा। हरियाणा ने फरवरी माह से पहले सप्ताह (5 फरवरी तक) 22 स्वर्ण, 15 रजत, 12 कांस्य पदक के साथ पहले पायदान पर बरकरार रहा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने एक बार फिर साबित किया है कि हरियाणा देश में खेलों की सुपर पावर है। प्रतियोगिताओं के परिणाम से स्पष्ट है कि हरियाणा में खेल प्रतिभाओं की भरमार है। इसलिए हम लगातार गांव-गांव खेल को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हम आगे भी हर खिलाड़ी को सब खेल सुविधाएं प्रदान करेंगे और हरियाणा को खेलों की नर्सरी बनाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की मज़बूत खेल नीति का यह परिणाम से जिससे यूथ गेम्स में एक के बाद एक स्वर्ण पदक आ रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को एक लाख, रजत मेडल विजेता को 60 हजार और कांस्य पदक लाने वाले खिलाड़ी को 40 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जबकि प्रतिभागी खिलाड़ी को प्रोत्साहन के रूप में पांच हजार रुपए दिये जाते हैं।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मध्य प्रदेश

पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के 8 शहरों में 11 फरवरी तक चले। 27 खेलों में देश के लगभग 6 हजार खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समाचार लिखे जाने तक हरियाणा ने बॉक्सिंग में 8 स्वर्ण समेत 15 पदक व एथलेटिक्स में 4 स्वर्ण, 4 रजत, 4 कांस्य मेडल जीते, जबकि निशानेबाजी में दो स्वर्ण, 3 रजत, 2 कांस्य व साइक्लिंग में 3 स्वर्ण, एक रजत जीता। बैंडमिंटन में दो स्वर्ण, वॉलीबाल में एक स्वर्ण, आर्चरी दो स्वर्ण पदक अब तक हासिल किए।

शेफाली वर्मा को बधाई

अंडर-19 टी20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान शेफाली वर्मा के रोहतक स्थित आवास पर पहुंचकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके परिजनों को मिठाई खिलाकर व पुष्प गुच्छ देकर बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की बेटी शेफाली वर्मा के नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अंडर-19 विश्वकप जीता है। इस ऐतिहासिक जीत पर बेटी शेफाली और पूरी क्रिकेट टीम पर प्रदेश व देश को गर्व है। मुख्यमंत्री ने इस युवा टीम को अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

इस मुलाकात के दौरान शेफाली वर्मा के दादा संत लाल वर्मा व पिता संजीव वर्मा ने भी मुख्यमंत्री का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। इस अवसर पर परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि शेफाली वर्मा के नेतृत्व में पहला महिला अंडर-19 टी20 क्रिकेट विश्वकप भारत के नाम हुआ है। हरियाणा की बेटी शैफाली वर्मा के नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए इंग्लैंड को हराकर विश्वकप जीता है। 29 जनवरी को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को सात विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत यह टूर्नामेंट जीतने वाला पहला देश बन गया।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद के सेक्टर-15 से जोशीमठ में भू-स्खलन से प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत सामग्री से भरे वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

फरीदाबाद में करीब 12.30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर चैरिटेबल अस्पताल का भूमि पूजन के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ।

अमृतकाल का 'निर्मल' बजट

विशेष प्रतिनिधि

केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल 45 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत करते हुए देश के हर वर्ग के हितों को साधने का प्रयास किया है। उन्होंने न केवल समाज के अंतिम छोर पर बैठे देशवासी का ख्याल रखा है बल्कि सात लाख रुपए तक की कुल कमाई करने वाले कर्मियों को भी आयकर में बड़ी राहत प्रदान की है। इन नागरिकों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। इनकम टैक्स स्लैब की संख्या भी घटाकर पांच कर दी गई है।

वित्त मंत्री ने पेश किए गए बजट में 'महिला बचत सम्मान योजना' लॉन्च करने का ऐलान किया। इससे महिलाएं बचत के लिए प्रोत्साहित होंगी। इसके तहत 7.5 फीसदी का सालाना ब्याज मिलेगा। किसानों के लिए 'श्री अन्न योजना' लॉन्च करने का ऐलान किया गया। इसके तहत मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।

श्री अन्न योजना के तहत बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मिलेट्स के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा मिलेट्स संस्थान की भी हैदराबाद में स्थापना की जाएगी। बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर वर्ष 10 हजार करोड़ रुपए की रकम जारी की जाएगी।

किस मंत्रालय का कितना हिस्सा

रक्षा मंत्रालय- 5.94 लाख करोड़ रुपए
सड़क परिवहन और राजमार्ग- 2.70 लाख करोड़ रुपए
रेल- 2.41 लाख करोड़ रुपए
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण- 2.06 लाख करोड़ रुपए
गृह मंत्रालय- 1.96 लाख करोड़ रुपए
रसायन और उर्वरक मंत्रालय- 1.78 लाख करोड़ रुपए
ग्रामीण विकास मंत्रालय- 1.60 लाख करोड़ रुपए
कृषि और किसान कल्याण- 1.25 लाख करोड़ रुपए
संचार- 1.23 लाख करोड़ रुपए
रक्षा मंत्रालय को मिलेंगे 5.94 लाख करोड़ रुपए

सैन्य उपकरण खरीदने की तैयारी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में रक्षा बजट में इजाफ़ा किया है। सरकार ने रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इससे पहले यह आंकड़ा 5.25 लाख करोड़ रुपए था। कहा जा रहा था कि तीनों सेनाओं की तरफ से भी फंड में इजाफ़े की मांग की जा रही थी। इसके अलावा सरकार बड़े स्तर पर सैन्य उपकरण खरीदने की तैयारी कर रहा है।

वेतनभोगियों को फायदे की उम्मीद

नवंबर 2022 तक भारत में वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या करीब 8.6 करोड़ के करीब थी। ऐसे केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से किए गए टैक्स स्लैब में बदलाव से करोड़ों वेतनभोगियों को फ़ायदा मिल सकता है। शहरों में रहने वाले वेतनभोगियों की भारत में औसतन सैलरी तीन लाख रुपए सालाना है।

अब 5 होंगे टैक्स स्लैब

नई टैक्स व्यवस्था में कुल सात लाख रुपए तक की कमाई वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा टैक्स स्लैब की संख्या अब सात से घटाकर पांच ही कर दी गई है। पहला स्लैब तीन से छह लाख तक का होगा, जिसमें पांच फीसदी टैक्स देना होगा। इसके अलावा दूसरा स्लैब छह से नौ फीसदी का होगा, जिसमें 10 फीसदी टैक्स लगेगा। वहीं तीसरा स्लैब 9 से 12 लाख का होगा, जिस पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख तक की कमाई पर 20 फीसदी टैक्स लागू होगा। वहीं, इससे अधिक की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लागू होगा।

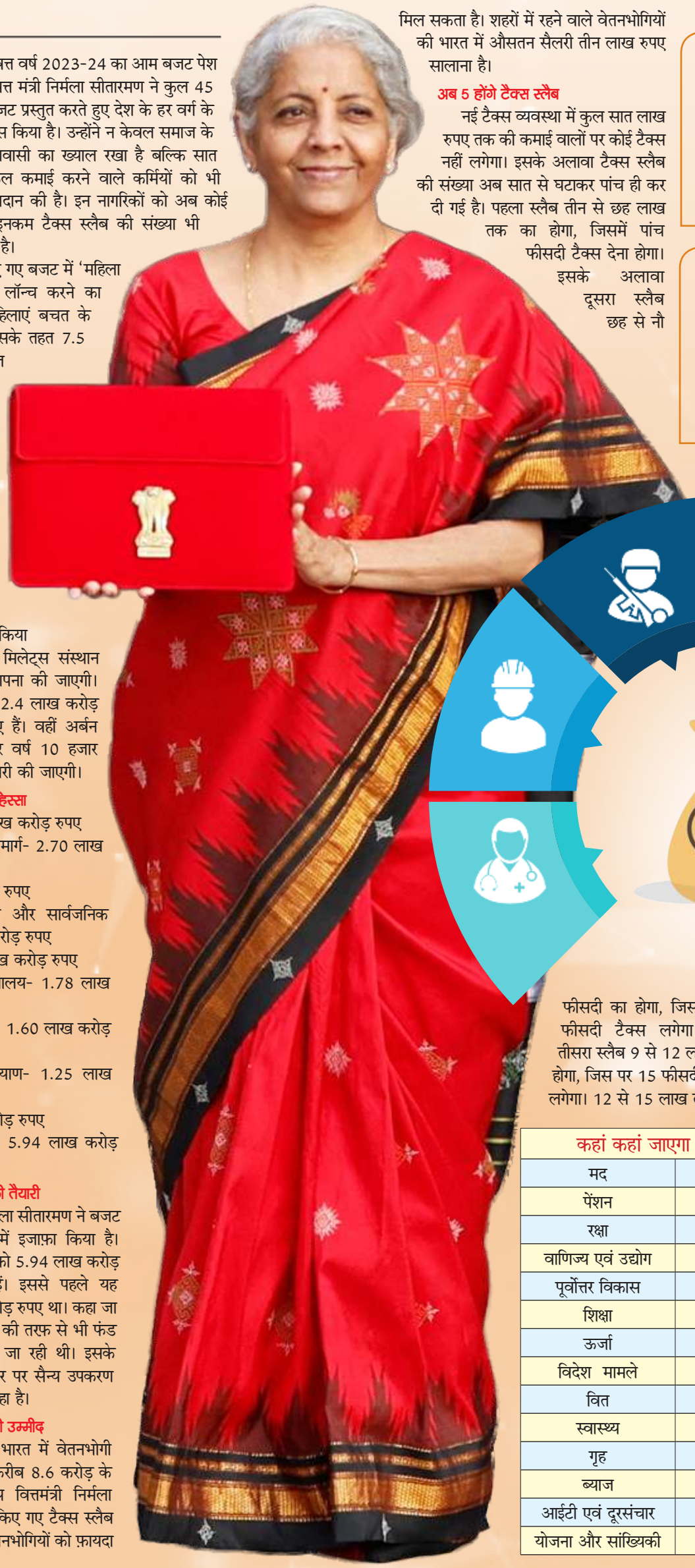

अमृतकाल के पहले बजट ने गरीबों एवं मध्यम वर्ग सहित आकांक्षी समाज के सपनों को पूरा करने के लिए एक मजबूत आधार स्थापित किया है। केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। यह बजट वंचितों को वरियता देता है। यह बजट आज के समाज के सभी वर्गों के सपनों को पूरा करने का काम करेगा।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

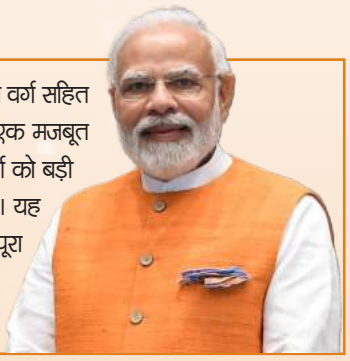

वित्त मंत्री ने समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर अमृत बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट देश के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। बजट में देश और समाज के प्रति जो 7 प्राथमिकताएं बताई हैं उनसे समाज के हर वर्ग का कल्याण होगा। आम बजट सुशासन, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और रोजगार सृजन का नया अध्याय लिखने में यह अहम योगदान देगा।

- मनोहर लाल, मुख्यमंत्री हरियाणा

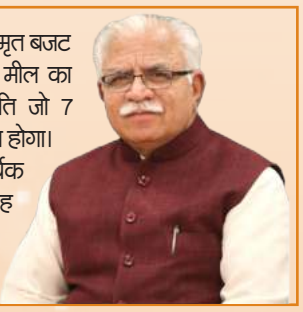

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा

वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए ज़्यादा फंड का आवंटन किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। वित मंत्री ने कहा कि लोगों को पुरानी गाड़ी पर स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत फ़ायदे भी दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बजट में डिजिटल इकॉनमी को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि डिजिलॉकर के इस्तेमाल में इजाफ़ा किया जाएगा। इसके अलावा पैन कार्ड को पहचान पत्र की मान्यता भी दी जाएगी।

गरीबों को राशन

कोरोना काल में यह तय हो गया था कि अनाज की वजह से कोई भूखा नहीं सोएगा। वितमंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। इसके अलावा 14 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 'पीएम किसान सम्मान निधि' के तहत मदद दी गई है। कोरोना काल में 80 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों को 28 महीने से मुफ़्त राशन दिया जा रहा है। अगले एक साल के लिए योजना का विस्तार किया गया है।

कहां कहां जाएगा पैसा, अनुमान

मद	राशि
पेंशन	234359
रक्षा	432720
वाणिज्य एवं उद्योग	48169
पूर्वोत्तर विकास	5892
शिक्षा	112899
ऊर्जा	94915
विदेश मामले	18050
वित	13574
स्वास्थ्य	88956
गृह	134917
ब्याज	1079971
आईटी एवं दूरसंचार	93478
योजना और सांख्यिकी	6268

ग्रामीण विकास	238204
वैज्ञानिक विभाग	32225
सामाजिक कल्याण	55080
कर प्रशासन	194749
राज्यों को अंतरण	324641
परिवहन	517034
केंद्र शासित	61118
शहरी विकास	76432
उर्वरक सब्सिडी	175100
खाद्य	197350
पेट्रोलियम	2257
कृषि	84214
पीएम किसान	60000
अन्य	120524
कुल जोड़	4503097

अंत्योदय परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए 'निरोगी हरियाणा योजना' शुरू की गई है। इसके तहत 25 मानकों के आधार पर गरीब व वंचित परिवारों की स्वास्थ्य जांच होगी।

अखिल भारतीय सिविल सेवा कबड्डी (पुरुष व महिला) खेल प्रतियोगिता का आयोजन 20 फरवरी से 24 फरवरी 2023 तक उत्तराखंड के देहरादून में करवाया जायेगा।

वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा को आ

आर्थिक प्रगति में तेजी से बढ़ रहा भारत

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में फरीदाबाद जिला के सूरजकुंड में 36वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ग्लोबल-इकोनॉमी के मामले में भारत विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन गया है, इसमें कला एवं शिल्पियों का अहम योगदान है।

धनखड़ ने कहा कि पहले हमारा देश जहां आर्थिक प्रगति के मामले में विश्व में 10 वें स्थान पर था वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब निरंतर तरक्की करते हुए 5वें स्थान पर आ गया है और जल्द ही अव्वल नंबर पर होगा। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिल रहा है।

उपराष्ट्रपति ने सूरजकुंड मेला को देश की विविध संस्कृतियों एवं कलाओं का संगम करार देते हुए कहा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन देशों की इस मेले में भागीदारी एक ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने भारत के उत्तर-पूर्व राज्यों की सांस्कृतिक महत्ता को देश के लिए गौरवशाली बताते हुए कहा इस मेले में पहुंचे इन राज्यों के कलाकार व शिल्पियों के रौनक से परिपूर्ण चेहरे दर्शा रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को प्रगति-पथ पर तेजी से अग्रसर किया है।

धनखड़ ने कहा हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध है। इस विरासत को देश-दुनिया के स्तर पर ले जाने में प्रदेश सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पर्यटन व अन्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है।

भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र 36 वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 के लिए थीम स्टेट रहा। जिसने इस क्षेत्र से विभिन्न कला, रूपों और हस्तशिल्प के माध्यम से अपनी अनूठी संस्कृति और समृद्ध विरासत का अनूठा प्रदर्शन किया। आगंतुकों को अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों से विरासत और संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिला। मेले के आगंतुकों के लिए, भाग लेने वाले विदेशी देशों के अंतरराष्ट्रीय लोक कलाकारों द्वारा भारत के राज्यों के कलाकारों सहित शानदार प्रदर्शन प्रस्तुत किए।

इनके अलावा मेले में राजस्थान के कच्ची घोड़ी, पंजाब के भांगड़ा, हरियाणा के लोक नृत्य, हिमाचल प्रदेश के जमकदा और नाटी, हिमाचल पुलिस बैंड, उत्तर प्रदेश के लोक नर्तक और सदाबहार बहरूपिया जैसे कलाकार मनोरंजन का केंद्र रहे। प्रमुख सचिव पर्यटन एम.डी. सिन्हा ने बताया कि मेले का आयोजन 43.5 एकड़ भूमि में किया गया। शिल्पकारों के लिए 1,179 वर्क हट्स और एक बहु-व्यंजन फूड कोर्ट बनाया जो बेहद लोकप्रिय रहीं।

सूरजकुंड शिल्प मेला 1987 में पहली बार हस्तशिल्प, हथकरघा और भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया था। केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति, विदेश मंत्रालय और हरियाणा सरकार के सहयोग से सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित, यह त्योहार अपने प्रदर्शन के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यटन कैलेंडर पर गर्व और प्रमुखता के स्थान पर आ गया है।

इस वर्ष करीब 40 देश मेले का हिस्सा रहे। इनमें शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शामिल हैं, जिसके तहत कजाकिस्तान, चीन, रूस, उज़्बेकिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया जैसे 25 से अधिक देश शामिल हैं। तुर्की, कंबोडिया, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, सऊदी अरब, कतर जैसे कुछ नाम बहुत उत्साह के साथ भाग लेंगे।

आकर्षण का केंद्र रही है हरियाणवी पगड़ी

फरीदाबाद में आयोजित 36 वें अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में सांस्कृतिक प्रदर्शनी में 'हरियाणवी पगड़ी' पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही। यहां पर 'पगड़ी बंधाओ, फोटो खिंचाओ' के माध्यम से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया। विरासत के निदेशक डा. महासिंह पूनिया ने बताया कि लोकजीवन में पगड़ी की विशेष महत्ता है। पगड़ी की परंपरा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। पगड़ी जहां एक ओर लोक सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ी हुई है, वहीं पर सामाजिक सरोकारों से भी इसका गहरा नाता है। हरियाणा के खादर, बांगर, बागड़, अहीरवाल, बृज, मेवात, कौरवी क्षेत्र सभी क्षेत्रों में पगड़ी की विविधता देखने को मिलती है। इस परिधान को सभी परिधानों में सर्वोच्च स्थान मिला।

खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता एवं प्रतिभागी विद्यार्थियों के लिए पहली अप्रैल से 31 दिसंबर, 2022 के दौरान खेल उपलब्धियों के आधार पर छात्रवृत्तियां देने के लिए 28 फरवरी, 2023 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्य के बहुतकनीकी संस्थानों, इंजीनियरिंग कॉलेजों व तकनीकी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए सिसको कम्पनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।

...े बढ़ाता सूरजकुंड मेला

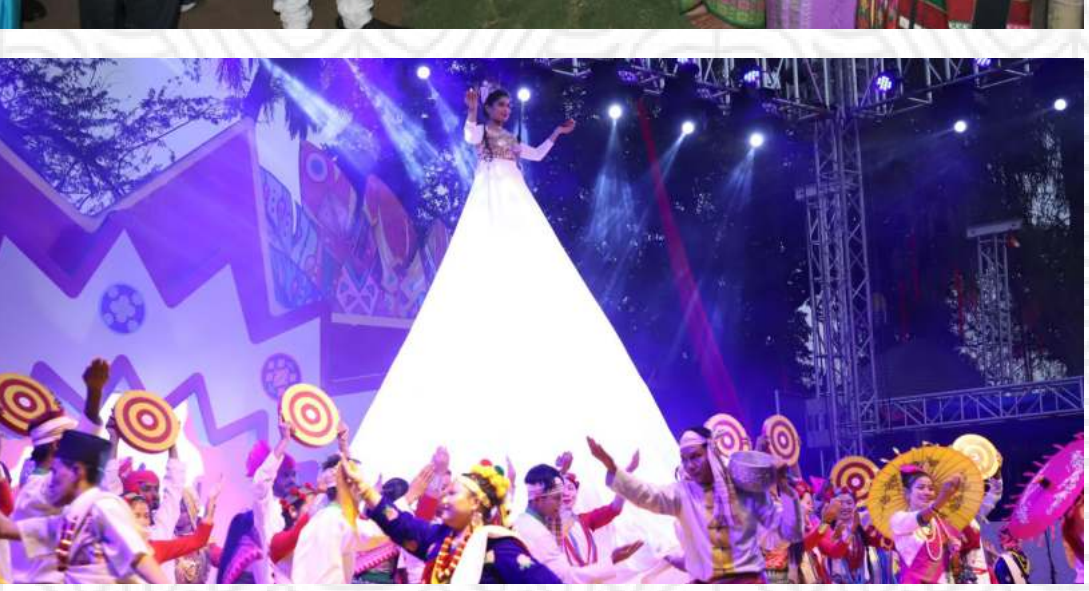

विविधता में एकता

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला हमारे देश की विविधता में एकता की कड़ियों को मजबूत करने के साथ-साथ 'वसुधैव कुटुम्बकम' की अवधारणा को भी आगे बढ़ाता है।

उन्होंने कहा कि देश-विदेश के कलाकारों व शिल्पकारों की कल्पनाओं से सराबोर कलाकृतियों से सुसज्जित इस हस्तशिल्प मेले की छटा देखते ही बनती है। इस तरह के मेले शिल्पकारों को अपनी पसंद व कला के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करते हैं। यह मेला हमेशा की तरह विविधता में एकता लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन कराता है।

आर्थिक आत्मनिर्भरता अहम : मुख्यमंत्री ने कहा कि सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेला और अन्य ऐसे मेले देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता में भी योगदान देते हैं। हम सभी को देश के शिल्पकारों द्वारा बनाई गई वस्तुओं पर गर्व करना चाहिए और उनके द्वारा बनाये गये उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा करके हम अपने क्षेत्र के शिल्पकारों तथा लघु उद्यमियों की मदद कर सकते हैं।

पर्यटन को बढ़ावा दे रही सरकार : उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन की नई अवधारणाओं पर भी काम किया है। हम फार्म टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रदेश में होम स्टे स्कीम भी शुरू की गई है। अब लोग, ख़ासकर छोटे किसान एक-दो कमरे बनाकर पर्यटकों को रख सकेंगे।

बिजली सुधारों के लिए सरकार ने कारगर कदम उठाए हैं और उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर ही समाधान करने के लिए बिजली पंचायतों का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है।

राज्य व केंद्र सरकार द्वारा एक समान उद्देश्य के लिए चलाई जा रही योजनाओं को एकीकृत करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा ताकि लाभार्थी को योजनाओं का लाभ मिल सके।

गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प

प्रदेश सरकार राज्य की गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर कदम उठा रही है। गौवंश के चारे के लिए हर वर्ष 30 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाता है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत जिले के कुराना गांव में स्थित श्री जगत गुरु ब्रह्मनंद गौशाला के वार्षिकोत्सव के अवसर पर उपस्थित गौभक्तों को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने गाय को चारा व गुड़ भी खिलाया। उन्होंने कहा कि गाय को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति तथा परंपराओं का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और उसकी पूजा की जाती है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत राजकीय पशुधन फार्म, हिसार में गोकुल ग्राम की स्थापना की जा रही है। हरियाणा गौ-सेवा आयोग द्वारा पंचकूला में हरियाणा गोवंश अनुसंधान केंद्र खोला गया है। इसमें अधिक फास्फेट युक्त आर्गेनिक खाद और वर्मीकम्पोस्ट पर अनुसंधान कार्य चल रहा है।

प्रदेश में 638 गौशाला की जा रही देखरेख : वर्तमान में प्रदेश में 638 गौशालाओं में गौवंश की देख-रेख में सरकारी प्रयासों के साथ-साथ सामाजिक संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। जिस भी रजिस्टर्ड गौशाला को अनुदान की ज़रूरत है वह अपनी मांग सरल पोर्टल पर डाल सकती है। इसके अतिरिक्त, 'मुख्यमंत्री गौशाला जगमग योजना' के अंतर्गत प्रदेश में 330 गौशालाओं में सोलर पावर प्लांट स्थापित किये गये हैं।

गौ पालन को प्रोत्साहन

प्रदेश में गौ-पालन को प्रोत्साहित करने के लिए देशी नस्ल की गाय, जैसे कि हरयाणा, साहीवाल, बेलाही, थारपारकर, गिर आदि की 20 पशुओं की डेरी स्थापित करने पर लाभार्थियों को गाय की खरीद हेतु लिये गये बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। देशी नस्ल की तीन व पांच गायों की डेरी खोलने वाले पशुपालकों को 50 प्रतिशत अनुदान भी दिया जाता है।

देशी गायों की नस्ल सुधार हेतु राज्य में 37 करोड़ रुपए की लागत से कैथल के क्योड़क , झज्जर के लकड़िया, करनाल के उचानी, और महेंद्रगढ़ में चार गोवंश संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई है। बेसहारा गोवंश को रखने के लिए गांव नैन (पानीपत) और गांव ढंढूर (हिसार) में दो गौ अभ्यारण्य स्थापित किए हैं।

मुख्यमंत्री ने गौशाला संचालकों से आह्वान किया कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गाय के गोबर और गोमूत्र से गोमूत्र प्राकृतिक फिनाइल, जैविक खाद, गोबर के बर्तन, प्राकृतिक पेंट, गमला, दीया, धूप, साबुन और अन्य उत्पादों के उत्पादन पर बल दें।

'मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना' में 26 नई सब्ज़ियां व फल शामिल

किसान को 'मेरी फसल- मेरा ब्यौरा' पर पंजीकरण अनिवार्य

संगीता शर्मा

फसल की अच्छी पैदावार के लिए मौसम की अहम भूमिका होती है। लेकिन कई बार बारिश, आंधी, तूफ़ान व सूखा होने से बागबानी किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने 'मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना' के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य राज्य में आपदाओं के कारण हुई फसल बर्बाद की भरपाई करने के लिए बीमा कवर राशि प्रदान करना है। जिससे किसानों को किसी भी परेशानियों व दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अब राज्य में इस सूची में नए 26 सब्ज़ियां, फलों व मसालों को शामिल किया गया है, जबकि पहले 20 शामिल थे। कुल मिलाकर अब इस सूची में 46 सब्ज़ियां, फलों व मसाले शामिल हैं, जिनका किसान बीमा करवाकर लाभ उठा सकते हैं।

पंजीकरण अनिवार्य

हरियाणा सरकार द्वारा बागवानी किसानों के हित में 'भावांतर भरपाई योजना' एवं 'मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना' चलाई जा रही है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान को 'मेरी फसल- मेरा ब्यौरा' (एम.एफ.एम.बी) पर पंजीकरण अनिवार्य है। किसानों को अपना 31 जनवरी, 2023 तक रबी फसलों को का पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है। 'भावांतर भरपाई योजना' के लिए अलग से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। 'मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना' का लाभ लेने के लिए पंजीकरण के साथ-साथ एम.बी.बी.वाई के पार्टल https://mbby.hortharyana.gov.in/. पर प्रीमियम भुगतान करके फसल का बीमा सुनिश्चित करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए जिला स्तर पर

जिला उद्यान अधिकारी से एवं टोल फ्री नंबर 18001802021 पर संपर्क कर सकते हैं।

नई सूची में 26 फसलें शामिल

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत 23 सब्ज़ियां, 21 फलों व 2 मसालों को शामिल किया गया है। अब कुल 46 सब्ज़ियां, फल व मसालें शामिल हैं। नई सूची में नौ अन्य सब्ज़ियों को भी शामिल किया गया है। इनमें कस्तूरी खरबूजा, तरबूज, लंबी तरबूज, गोल तरबूज, तुरई, कद्दू, खीरा, समर स्क्वैश, अरबी है। इसके अतिरिक्त 17 फलों को नई सूची में शामिल किया गया है। इनमें ड्रैगन फल, अंजीर, खजूर, अनार, माल्टा, मौसम्बी, नींबू, नारंगी, आड़ू, नाशपाती, बेर, आंवला, चीकू, जामुन, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, लीची हैं।

कुल 46 फसलों का बीमा

अब इस योजना के अंतर्गत सब्जियों में टमाटर, प्याज, आलू, गोभी, मटर, गाजर, भिंडी, लौकी, करेला, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, मूली, कस्तूरी तरबूज, तरबूज, लंबे तरबूज, गोल तरबूज, तुरई, कद्दू, ककड़ी, ग्रीष्मकालीन स्क्वैश, अरबी शामिल है। इसके अतिरिक्त फलों में किन्नू, अमरूद, आम, बेर, ड्रैगन फल, अंजीर, खजूर, अनार, माल्टा, मौसम्बी, नींबू, नारंगी, आड़ू, नाशपाती, बेर, आंवला, चीकू, जामुन, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, लीची और दो मसाले हल्दी, लहसुन शामिल हैं।

सुरक्षा कवच उपलब्ध

इस योजना के तहत सब्ज़ियों, फलों और मसाले की फसलों को सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिला के किसानों के लिए इस योजना के तहत फलों की खेती पर 40 हजार रुपए प्रति एकड़ सब्ज़ियों व मसालों पर 30 हजार रुपए प्रति एकड़ का बीमा किया जाता है। इसके लिए किसान को फलों की खेती पर एक हजार प्रति एकड़ एवं सब्ज़ियों व मसालों पर 750 रुपए प्रति एकड़ का प्रीमियम भुगतान करना होगा। योजना के तहत बीमा दावे का निपटारा करने के लिए सर्वे किया जाएगा जिसके तहत फसल नुकसान को 26 से 50 प्रतिशत 50 से 75 प्रतिशत और 75 से 100 प्रतिशत में आंका जाएगा। हालांकि इसमें रजिस्ट्रेशन की समय की शर्त जोड़ी गई है यानि तय समय सीमा में रजिस्ट्रेशन कराने पर ही नुकसान की बीमा राशि दी जाएगी।

तयशुदा समय पर करवाएं पंजीकरण

लौकी, करेला, फूल गोभी, अमरूद, भिंडी, बैंगन, ककड़ी, टिंडा, तोरई, कद्दू, खीरा व अरबी के लिए किसान 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पंजीकरण करवाएं। खरीफ प्याज के लिए 1 अगस्त से 25 सितंबर तक, अमरूद बरसाती के लिए 1 अप्रैल से 31 मई तक, अमरूद शीतकालीन व बेर के लिए 1 सितंबर से 31 अक्तूबर तक, ड्रैगन फल व हल्दी के लिए 1 मई से 31 जुलाई तक, अनार, मालटा, नींबू, संतरा, आंवला व किन्नू के लिए 1 मार्च से 31 मई तक पंजीकरण करवाएं। आड़ू, नाशपाती, आलूबुखारा, जामुन, अंगूर, लीची, अंजीर, खजूर व आम के लिए 1 फरवरी से 31 मई तक, चीकू के लिए 1 सितंबर से 30 नवंबर तक, स्ट्रॉबेरी के लिए 1 सितंबर से 31 जनवरी तक, टमाटर, आलू, फूल गोभी, गाजर, पत्ता गोभी, मूली, लहसुन के लिए 15 सितंबर से 31 जनवरी तक, रबी प्याज के लिए 15 सितंबर से 31 जनवरी, जुकिनी के लिए 15 नवंबर से 31 जनवरी तक भिंडी, लौकी, करेला, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, टिंडा, तोरई व कद्दू के लिए 15 जनवरी से 15 मार्च तक पंजीकरण करवाएं।

किसानों को होगा फ़ायदा

महेंद्रगढ़ के प्रगतिशील किसान भ्रम प्रकाश का कहना है कि 'मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना' में अन्य सब्ज़ियों व फलों को शामिल करने से किसानों को लाभ होगा। इससे अब प्राकृतिक आपदा आने में उनकी फसलों का मुआवज़ा मिल सकेगा। गुरुग्राम के प्रगतिशील किसान

जितेंद्र कुमार का कहना है कि किसान की फसल प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि मौसम अच्छा होता है तो फसल की पैदावार अच्छी होती है और किसानों को फ़ायदा होता है। जबकि कई बार मौसम की मार से किसानों को आर्थिक तंगी को सहना करना पड़ता है। उनका कहना है कि हरियाणा सरकार की योजनाओं से किसानों को फ़ायदा मिल रहा है। नूह के किसान रौनक

सिंह जमील अहमद और हिसार के भिखू मोयल का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना' के

अंतर्गत इस सूची में नए 26 सब्ज़ियां व फलों को शामिल किया गया है, जबकि पहले 20 शामिल थे। कुल मिलाकर अब इस सूची में 46 सब्ज़ियां, फलों व मसाले शामिल हैं, जिनका किसान बीमा करवाकर लाभ उठा सकते हैं। इससे किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाली फसलों के नुकसान का मुआवज़ा मिल सकेगा।

राष्ट्रीय कैंसर संस्थान-एम्स, बाढसा जल्द ही द्वारका एक्सप्रेस-वे के माध्यम से दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से जुड़ेगा। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के निर्माण से इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा।

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को विभाग से संबंधित संगठनात्मक संरचना को युक्तिसंगत बनाने व सर्विस रूल्स को संशोधित करने संबंधित रिपोर्ट सीधे रेशनलाइजेशन कमीशन को भेजने के निर्देश दिए हैं।

2025 तक प्रदेश होगा टीबी मुक्तः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत टीबी रोग से ग्रस्त पांच मरीजों को गोद लिया और उन्हें टीबी किट प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के संकल्प के तहत हरियाणा को टीबी मुक्त बनाने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। इन सार्थक प्रयासों से हरियाणा-टीबी मुक्त लक्ष्य को वर्ष 2025 तक ही पूरा कर लिया जाएगा।

मनोहर लाल ने प्रदेश के उद्योगपतियों, प्रशासनिक अधिकारियों, शैक्षिक संस्थानों, सामाजिक संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों और निर्वाचित प्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि वे इस पुनीत कार्य से जुड़ें और टीबी रोगियो को गोद लेकर उन्हें पोषाहार एवं उनके परिजनों को भावनात्मक एवं सामाजिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए आगे आएं।

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति या संस्था वेब पोर्टल communitysupport.nikshay.in के माध्यम से अपना पंजीकरण करके निक्षय मित्र के रूप मे शामिल होकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकती है। पंजीकरण के बाद भोगोलिक स्थितियों के अनुसार टीबी मरीज का चयन भी कर सकती हैं। उसके बाद गोद लेकर मरीज के इलाज पर लगभग एक वर्ष तक मासिक स्पोर्टिव डाइट के रूप में 400 से 500 रुपए की राशि से रोगी का इलाज करने में सहायता प्रदान कर सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर स्तर पर जन सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए सभी नागरिक टीबी रोग उन्मूलन कार्यक्रम में अपनी सहभागिता से टीबी मुक्त हरियाणा बनाने में अपेक्षित सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने आशा जताई की हरियाणा प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को 2025 तक प्राप्त करने की प्रतिबद्धता में सक्षम होगा। हम सब मिलकर हरियाणा प्रदेश को टीबी मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कार्य करें।

- संवाद ब्यूरो

एलोपैथी के साथ आयुष उपचार

मनोज प्रभाकर

एलोपैथी चिकित्सा के बारे में धारणा है कि इसमें रोगी को अपेक्षाकृत परिणाम जल्द मिलता है, जबकि आयुर्वेद के बारे में कहा जाता है कि इसके जरिए परिणाम भले ही कुछ विलंब से मिलता हो लेकिन उपचार स्थाई होता है। रोग की तासीर के मुताबिक अगर मरीज को इन दोनों चिकित्सा पद्धतियों का सहयोग मिल जाए तो रोग निदान सहज हो जाता है। हरियाणा सरकार इस सुविधा के लिए कुछ नया करने जा रही है। हरियाणा के मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस के पाठ्यक्रम में आयुर्वेद के कुछ आवश्यक विषयों को शामिल करने की योजना है। इसके अलावा प्रदेश के तमाम छोटे-बड़े चिकित्सा संस्थानों में आयुर्वेद के अलावा होम्योपैथी व अन्य पैथियों की चिकित्सा सुविधा मयस्सर कराई जाएगी ताकि मरीजों को एक तरह से मुक्कमल उपचार उपलब्ध हो सके।

आयुष को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति का ऐलान किया गया है। नीति का नाम है-'पॉलिसी फॉर सर्टिफिकेशन एंड स्टेंडर्डाईजेशन ऑफ आयुष फैसीलिटिज'। हिंदी में जानें तो आयुष सुविधाओं के प्रमाणन और मानकीकरण के लिए नीति। यह नीति आगामी 31 अक्तूबर, 2027 तक लागू रहेगी। नीति से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है।

स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य चिकित्सा ढांचे को समग्र रूप से विकसित करना है। निजी क्षेत्र में आयुष औषद्यालयों/ क्लीनिकों, पंचकर्म केंद्रों, आयुष अस्पतालों की पहचान कर उनके संचालन के लिए प्रभावी आयुष चिकित्सा सेवाओं को शुरू कराया जाएगा।

राज्य सरकार व्यापक स्वीकृति के साथ आयुष प्रणाली को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। आयुष अस्पतालों, वेलनेस सेंटरों आदि को पर्याप्त मान्यता प्रदान की जाएगी। आयुष विभाग, हरियाणा सरकार के तहत मान्यता प्राप्त/प्रमाणित आयुष सुविधाओं/ संस्थानों की तीन श्रेणियां होंगी जिसमें आयुष हीरक, आयुष स्वर्ण और आयुष रजत शामिल है।

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा पूर्ण मान्यता प्राप्त करने वाले अस्पतालों, वेलनेस सेंटर आदि को राज्य सरकार द्वारा फाइव स्टार रेटिंग के साथ आयुष स्वर्ण के रूप में मान्यता दी जाएगी। जिन आयुष संस्थाओं ने अपनी संबंधित श्रेणी में एनएबीएच द्वारा मानक प्राप्त किए हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा थ्री स्टार रेटिंग के साथ आयुष रजत के रूप में मान्यता दी जाएगी। अपनी श्रेणी में आयुष स्वर्ण मान्यता/ प्रमाणन प्राप्त करने के बाद लगातार पांच वर्षों तक एनएबीएच मान्यता बनाए रखने वाली आयुष संस्थाओं को सेवन स्टार रेटिंग को 'आयुष हीरक' के रूप में मान्यता दी जाएगी।

आवेदन करने वाली फर्मों और कंपनियों को भारत में लागू कानूनों के तहत पंजीकृत होना चाहिए। संस्था के पास वैध जीएसटी नंबर और पैन होना चाहिए। जिस पंजीकरण के तहत योजना है उससे कोई अन्य व्यवसाय संचालित नहीं किया जाएगा। आवेदकों को महानिदेशक आयुष, हरियाणा में 5,000 रुपए के आवेदन शुल्क के साथ आवेदन करना होगा।

आयुर्वेद भी पढ़ेंगे एमबीबीएस के विद्यार्थी

स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में एमबीबीएस पाठयक्रम में आयुर्वेद को भी शामिल किया जायेगा। एमबीबीएस की डिग्री के तहत चार साल विद्यार्थी एलोपैथिक की पढ़ाई करेगा, वहीं एक साल आयुर्वेद की भी पढ़ाई करेगा, इसके लिए एक टीम का गठन किया है जो पाठ्यक्रम तैयार करेगी।

आयुष को बढ़ावा देने के लिए कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय बनाया गया है। इसमें आयुर्वेद के अलावा योगा, यूनानी, सिद्धा व होम्योपैथी शामिल हैं। इन पांचों संकायों पर कार्य हो रहा है। पंचकूला में लगभग 270 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान बनाया जा रहा है। आगामी दिसंबर माह तक यह तैयार हो जायेगा। नूह में यूनानी चिकित्सा पद्धति का कालेज बनाया गया है तथा अंबाला छावनी में होम्योपैथिक कालेज व देवरखाना में प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल बनाया जा रहा है।

कैंसर लाइलाज नहीं मगर सजगता ज़रूरी

कैंसर के बारे में ज़ागरूकता बढ़ी है लेकिन जो बढ़ी है वह नाकाफ़ी है। चिकित्सा से जुड़ी सामाजिक संस्थाओं व राज्य सरकारों को चाहिए कि इस गंभीर बीमारी के बारे में न केवल ज़ागरूकता बढ़ाई जाए बल्कि इससे पीड़ित मरीजों को अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। कैंसर लाइलाज नहीं है लेकिन बायोप्सी, कीमोथैरेपी व सर्जरी आदि उपचार से जुड़ी आधी-अधूरी जानकारी मरीजों व उनके तीमारदारों को सही निर्णय लेने के लिए परेशानी में डाल देती हैं। यह सत्य है कि शुरुआती स्तर पर रोग की पहचान हो जाए तो इसकी गंभीरता से बचा जा सकता है लेकिन यह शुरुआती स्टेज कब और कैसे पहचानी जाए, बड़ा सवाल है। इसके बारे में चिकित्सा संस्थानों में अलग से प्रभाग बनाए जाने की जरुरत है ताकि कैंसर रोग निदान केंद्रों में भीड़ जमा न हो सके। इतना ही नहीं, शुरुआती स्टेज के कैंसर के निदान के लिए भी एलोपैथी के अलावा अन्य पैथियों में उपचार की जानकारी देने की सख़्त ज़रुरत है।

शरीर में कोशिकाओं के बनने व नष्ट होने की प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। इस निरंतरता में कोई गड़बड़ी होने से बीमार कोशिकाएं अनियंत्रित ढंग से बढ़ने लगती हैं, जो एक जगह जमा होकर ट्यूमर का रूप लेने लगती हैं। कई बार ये एक उभार या गांठ के रूप में दिखाई देने लगती है।

शोध के मुताबिक पौष्टिक खान-पान, सक्रिय जीवन शैली व वजन को नियंत्रित रखने से कैंसर के जोखिम को कम रखा जा सकता है। इनके अलावा वसा, चीनी और मांस का सेवन कम करें, पादप उत्पाद अधिक खाएं, नियमित व्यायाम करें, शराब, धूम्रपान व तंबाकू का उपयोग न करें, तनावमुक्त जीवन के लिए आवश्यक उपाय अपनाएं, अगर किसी को कैंसर की शिकायत है तो नियमित जांच कराएं।

जानकारी के मुताबिक 30 से 50 प्रतिशत कैंसर के कारण जीवनशैली से जुड़ें हैं। तंबाकू, शराब, पोषण की कमी, रेडियशन व रसायनों से संपर्क, सूर्य की रोशनी में बहुत कम समय बीताना, औद्योगिक प्रदूषण, वायरस, हार्मोन असंतुलन आदि कई ऐसे कारण हैं जो इस रोग के जोखिम को बढ़ाते हैं। इनके प्रति सजग रहकर ही खतरे को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि खासकर ग्रामीण महिलाएं अपने शरीर की परेशानियों के बारे में बताने में संकोच करती हैं, उनको चाहिए कि वे डॉक्टर के पास जाएं और खुलकर बात करें।

ये लक्षण हों तो न बरतें असावधानी

यदि किसी को खाना निगलने में परेशानी हो, मुंह में बार-बार छाले होते हों, खाना अटकता हो, पेशाब की आदत में बदलाव हो गया हो, पेशाब रूक-रूक कर आता हो, लंबे समय तक खांसी का रहना, खांसने पर खून आना, महिलाओं में गंदे पानी की शिकायत, अपच, पेट का फूलना और बच्चों में बुखार का लंबे समय तक रहना, वज़न का कम होना, भूख ना लगना इत्यादि कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इनके लिए डॉक्टर से संपर्क करें।

पीजीआईएमएस के ओंकोलोजी विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉ. संजीव प्रसाद ने ओपीडी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कैंसर के प्रति लोगों को ज़ागरूक करने का प्रयास किया। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. ईश्वर सिंह ने कहा कि कैंसर अब लाइलाज नहीं रहा है, बशर्ते हम उसका समय पर इलाज करवाएं। डॉ. ईश्वर ने कहा कि हमें कैंसर से डरना नहीं है अपितु उसको मिलकर हराना है।

कैंसर पर और अनुसंधान की जरूरतः विज

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए अनुसंधान हेतु एक कमेटी का गठन जल्द किया जाएगा। यह कमेटी कैंसर के मरीजों की हिस्ट्री को रिकार्ड करेगी और अनुसंधान के अन्य जो भी तरीके होते हैं उनको अपनाकर इस पर अध्ययन/रिसर्च करवाई जाएगी। उन्होंने कहा रोहतक पीजीआई को इस ओर कारगर कदम उठाने चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अंबाला कैंट में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल बनाया है और लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है। अस्पताल में अब तक लगभग 125 के आस-पास सफलतापूर्वक ऑपरेशन किए जा चुके हैं और आस-पास के पड़ोसी राज्यों के मरीज भी यहां आ रहे हैं।

शस्त्र लाइसेंस के लिए सरल केंद्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। आवेदक को केवल 2,100 रुपए खर्च करने होंगे जिनमें से 1,500 रुपए प्रशिक्षण के, 500 रुपए आवेदन के व 100 रुपए अटल सेवा केंद्र के होंगे।

नूंह और पलवल के हथीन और होडल खण्ड में खसरा रूबेला (एमआर) कैच-अप अभियान को चलाया जा रहा है, जिसके तहत इस अभियान में 9 माह से 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को एमआर के टीके की एक अतिरिक्त खुराक दी जाएगी।

सुशासन से निकली शिक्षा संस्कृति

मनोज प्रभाकर

हरियाणा की समृद्ध संस्कृति में शिक्षा संस्कृति शुमार हो गई है। प्रदेश के वर्तमान परिदृश्य पर नजर डालें तो शिक्षा के क्षेत्र से एकाध प्रतिभा नहीं बल्कि अनेक प्रतिभाएं निकलकर आ रही हैं। पूरे प्रदेश में पढ़ने-पढ़ाने का माहौल बना है। परीक्षा चाहे स्कूल कालेज की हो या प्रतियोगी परीक्षा, हर परीक्षा में विद्यार्थी श्रेष्ठ परिणाम दे रहे हैं। हर संकाय में निपुणता सामने आ रही है।

यह सब संभव हुआ वर्तमान प्रदेश सरकार की नीतियों की वजह से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब पहली बार प्रदेश की बागडोर संभाली उसी समय उन्होंने सुशासन का संकल्प लिया था। इरादे स्पष्ट कर दिये थे कि अब प्रदेश में जो भी विकास होगा, पारदर्शी होगा। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबको साथ लेकर साथ चला जाएगा। न कोई क्षेत्रवाद होगा और न कोई भाई-भतीजावाद। इन संकल्पों के चलते वे आगे बढ़े और अनेक प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद अपने अभियान पर डटे रहे।

उनके मुख्यमंत्री बनने से पूर्व प्रदेश के हालात असामान्य थे। राजकीय क्षेत्र में हर प्रकार के वाद का बोल-बाला था। सामान्य लोगों की कोई सुनवाई नहीं थी। सरकारी नौकरियां केवल पहुंच वालों के लिए थी। काबिलियत का कोई मूल्य नहीं था। नौकरियों में ट्रांसफर एक व्यवसाय बन चुका था। इन सबके चलते जनप्रतिनिधियों के आगे पीछे लोगों की भागमभाग लगी रहती थी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 'सुशासन' का संकल्प लेते हुए इन सभी कार्यों पर रोक लगा दी और एलान कर दिया कि सभी नौकरियां 'बिन पर्ची व बिन खर्ची' के लगाई जाएंगी। सुशासन धीरे-धीरे आगे बढ़ा। आज उसके परिणाम सबके सामने हैं। प्रदेश के छात्र छात्राओं में पढ़ने-पढ़ाने की बात होने लगी है। अभिभावक भी अब किसी जुगाड़ के चक्कर में न रहकर बच्चों के साथ सलेबस की बात करने लगे हैं।

सच मानिये पहले तो यही पता नहीं लगता था कि उच्च पदों वाली नौकरियां लगती कैसे हैं। अब तो सामान्य व गरीब परिवार के बच्चों को भी अचानक खबर मिलती है कि उनका आईएएस, एचसीएस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, अध्यापन या अन्य उच्च पदों के लिए चयन हो गया है। वो भी बिना किसी सिफारिश और बिना किसी लेन देन के।

हरियाणा सिविल सेवा का परिणाम घोषित

हरियाणा लोक सेवा आयोग ने हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) और अन्य संबद्ध सेवा परीक्षा-2021 का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने पर्सनेलिटी टेस्ट/साक्षात्कार के लिए उपस्थित सभी 423 उम्मीदवारों के अंतिम अंकों को प्रदर्शित किया है। आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणियों में कुल 155 उम्मीदवारों की सिफारिश की है। इन उम्मीदवारों में 48 एचसीएस (कार्यकारी), 7 डीएसपी, 14 ईटीओ, 5 डीएफएससी, 4 ए श्रेणी के तहसीलदार, 5 एईटीओ, 46 बीडीपीओ, 3 ट्रैफिक मैनेजर्स, 2 डीएफएसओ और 21 असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं।

24 जुलाई, 2022 को सामान्य अध्ययन (100 अंक) और सीएसएटी (100 अंक) की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी। लगभग 40,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। 2018 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए • ालीफाई हुए। मुख्य परीक्षा अक्त ूबर और नवंबर, 2022 में आयोजित की गई थी।

मुख्य परीक्षा में हिंदी (100 अंक), अंग्रेजी (100 अंक), सामान्य अध्ययन (200 अंक) और 1 वैकल्पिक पेपर (200 अंक) शामिल हैं। उम्मीदवारों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में न्यूनतम 33 प्रतिशत के साथ कुल मिलाकर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने थे। 425 उम्मीदवारों ने पर्सनेलिटी टेस्ट/साक्षात्कार के लिए • ालीफाई किया।

425 अभ्यर्थियों का पर्सनेलिटी टेस्ट/साक्षात्कार 30 जनवरी से 5 फरवरी, 2023 तक आयोग के कार्यालय में आयोजित किया गया था। आयोग ने 5 फरवरी को 675 अंकों (मुख्य परीक्षा के 600 +साक्षात्कार के 75) में से उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त फाइनल अंकों की घोषणा की। आयोग ने 155 उम्मीदवारों को उनके काडर सहित, उनकी मैरिट, वरीयता और सीटों की उपलब्धता के आधार पर आवंटन की सिफारिश की है।

सुण छबीले बोल रसीले

रोकना होगा पानी का अनावश्क दोहन

छबीला - रसीले के सै आज की खास खबर?

- भाई खबर यो सै अक जोशीमठ के बहुत सारे मकानां में मोटी मोटी दरार आगी जिसके चलते लोगां नै मकान और गाम छोड़ने पड़गे।

- भाई लागै सै यो प्राकृतिक आपदा सै। भगवान के आगै किसकी चालै सै।

- भाई छबीले, सुणने में यो आवै सै अक उड़े के पहाड़ां में बडे-बडे प्रोजेक्ट चाल रे सैं। उन प्रोजेक्टां के चालते बतावैं से पहाड़ी एरिये का बोहत सा पानी उरेन-परेन होग्या। पहाड़ां नै तो इतणी मार भतेरी। उनका आपणा-आपणा ठिकाणा हिलग्या और मकानां में दरार आगी। जिसके चलते प्रशासन नै बहुत से मकान तो खुद गिराने पड़े, ताकी कोई हादसा ना होज्या।

- भाई रसीले, कुदरती व्यवस्था में छेड़छाड़ होज्या तो नुकसान होणे के चांस होज्यां सैं।

- दूर क्यों जा सै। आपणे गाम में देखले। कितणे मकान सैं जिनकी दिवारां में तरेड़ आ री सैं?

- निरें सैं भाई। पर आड़ै तो पहाड़ कोन्या, इन मकानां में तरेड़ क्यूं आई?

- जो कारण जोशीमठ में हो सकै सै वो आड़ै भी हो सकै सै।

- वो क्यूकर?

- वो न्यू, अक गाम के हर तीसरे मकान में सबमर्सिबल लागर्‌या सै। ऊपर तैं सरकार नै चौबीस घंटे बिजली दे दी। लोगां नै न्हाणा हो, कपड़े धोणे हों, बर्तन मांजणे हों, ढोर डांगरां ताहीं पाणी पिलाणा हो, उनको नहलाणा हो, छोटी मोटी क्यारी में पाणी देणा हो, गाड़ी या ट्रैक्टर धोणे हों, और तो और गली साफ करणी हो, तो लोग बटन दबावैं सैं और एक झटके में हजारों लीटर पानी धरती तैं बाहर काढ दे सैं। धरती के भीतर तैं इतणा पाणी लिकड़ैगा तो धरती माता शांत कैसे रह पावैगी? उसकै भी पीड़ा होवैगी, जिसके चलते थोड़ी बहुत हलचल लाजमी सै।

- हां भाई रसीले, बहुत से माणस तो पड़ौसियां कै सिर होज्या सैं। न्यू कहैं सैं अक थारी नाली का पानी म्हारी भींत में मरैं सै, आपणे सिस्टम नै ठीक करल्यो। कसूर या कमी चाहे आपणे कानी हो, पर दोष पड़ौसी में टोवैंगे।

- ज़रूर भाई छबीले, एक बात और सै गामां में पहल्यां के जो मकान सैं उनकी दिवारां में तो तरेड़ ज़रूर पावैं सैं। पहल्यां जिब मकान बणाया करते तो डीपीसी, बीम, लेंटर या किसे प्रकार का लोहा इस्तेमाल ना कर्‌या करते। जिसकी वजह तैं यो परेशानी इैब दिखाई दे री सैं।

- भाई गामां में सबमर्सिबल लगाणे के बारे में प्रशासन की ओर तैं कोए खास नियम-कायदा कोन्या। केवल शहरां में सुणाई दे सैं वो भी बहुत कम। वरना सही मायने में देख्या जा तो एक सबमर्सिबल पूरी गली के मकानां ताहीं पाणी दे सकै सै। उसका पानी सारे मिल-जुलकै बरत

सकैं सैं। पर कोन्या, किसे कै इस बात की ना तो सुहाण और ना नीयत। लोगां धौरै पीस्सा इतणा होर्‌या सै अक नया घर बणाण तैं पहल्यां सबमर्सिबल लगवाएं पावैं सैं। लगाण आले भी तौला ए लगा दे सैं। कायदा कानून उन धोरै भी कोन्या।

- भाई ना तो कुएं रहे और ना हाथ के नलके। सब सबमर्सिबल चलावैं सैं। मेरे ख्याल सै खेतां में ट्यूबलां का इतणा पानी कोन्या निकलता। पहल्यां गामां के जोहड़ सूख जाया करते, ईब कदे नहीं सूखते।

- छबीले इस सरकार नै 'हर घर नल से जल' योजना चला राखी सै। योजना बढ़िया सै, लोगां कै काम भी आ री सै। पर इसके ज़रिए पाणी का दुरुपयोग भी बोहत हो सै। टोंटी खाली चाले जांगी लेकिन उननै बंद करण की हिम्मत कोई नहीं करता। गामां में विभाग का कोई कर्मचारी भी नज़र नहीं आता जो इन चालती टोटियां नै बंद कराणे के बारे में लोगां नै ज़ागरूक कर सकै। पंचायती प्रतिनिधियां नै चाहिए कि वे इस ओर ध्यान दें। लोगां नै भी खुद चाहिए कि वे पानी का अनावश्यक दोहन ना करैं। जितणी ज़रूरत हो उतणा पाणी बरतो, ना ज़रूरत हो तो उसनै बंद करद्यो।

- हां भाई, ज़मीन का पानी बोहत तेजी तै बदलण लागर्‌या सै। जिस ज़मीन का पाणी मीठा होया करता उस ज़मीन का पाणी खारा हो लिया, और होण लागर्‌या सै। ज़रूरत के हिसाब तैं नहरां में भी पूरा पाणी कोन्या।

-चाहे सबमर्सिबल का पाणी हो या नहरी पानी की सप्लाई वाला पाणी, दोनों का इस्तेमाल उतणाए करैं जितणी ज़रूरत हो। यो काम करवाणे के लिए कोई सरकार घरां कोनी आवै। यो काम तो खुद करणा होगा। समय रहते जै हामनै इस तरफ़ ध्यान नहीं दिया तो म्हारी आणे वाली पीढ़ी गंभीर संकट में पड़ज्यांगी। पेयजल के संकट के चलते हो सकै सै उननै गाम छोड़कै कितै और जाणा पड़ज्या।

- मनोज प्रभाकर

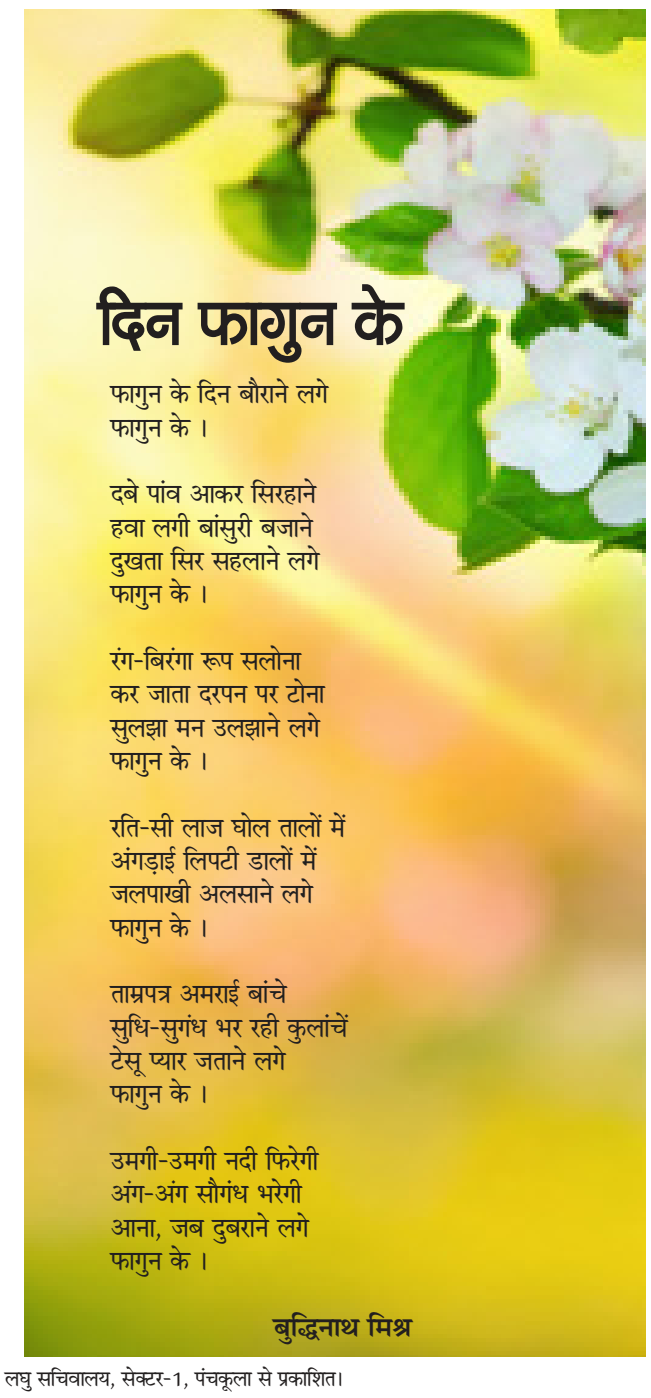

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com